

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून दिनांक 21 नवम्बर, 2007

विषय: स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत चालू वृहद निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 30136/ 5(ख)1/भ0नि0/1/2007-08 दिनांक 07 अगस्त, 2007 एवं संख्या 5(ख)1/41033/एस0सी0पी0/2007-08 दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 के संबंध में तथा शासनादेश सं0 25/XXIV-3/2006 दिनांक 25 जनवरी, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित 09(नौ) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्तम्भ-3 पर अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ-4 पर पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए कालम-5 पर अंकित विवरणानुसार कुल रू0 257.14 लाख (रुपये दो करोड सतावन लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या 1010/XXIV-3/2007/02(20)07 दिनांक 03 अगस्त, 2007 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपयों में)

क्र.स	विद्यालय का नाम	अनुमोदित लागत	अब तक स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1.	रा0इ0का0, मेहरावना, देहरादून	83.43	52.00	31.43
2.	रा0इ0का0 कवानुमंझगांव, देहरादून	78.72	42.00	36.72
3.	रा0इ0का0 सावंडा, देहरादून	79.60	52.88	26.72
4.	रा0इ0का0 बिलखेत, पौड़ी	68.19	48.19	20.00
5.	रा0इ0का0 गुलियारी, पौड़ी	85.73	12.00	43.73
6.	रा0उ0मा0 वि0मोल्डाडी, उत्तरकाशी	78.14	52.00	26.14
7.	रा0इ0का0 थाती (धनारी), उत्तरकाशी	79.75	59.75	20.00
8.	रा0उ0मा0 वि0पौटी, उत्तरकाशी	84.40	22.00	32.40
9.	रा0उ0मा0 वि0 मालनाधार, उत्तरकाशी	82.72	62.72	20.00
	योग			257.14

अर्पण

- (1) उल्लिखित विद्यालय अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बाड़ों में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।
 - (2) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
 - (3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
 - (4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। उक्त कार्यों को समयबद्ध ढंग से, इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायगा।
 - (5) एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।
 - (6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य-नजर एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
 - (7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से अवश्य कर लें। निरीक्षण के उपरान्त स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
 - (8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
 - (9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
 - (9) यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।
 - (10) जी०पी०डब्लू फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
 - (11) किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दें एवं डिग्री कालेजों/मेडिकल के हास्टलों का निर्माण एच०आई०सी० के मानकों के आधार पर प्रारम्भिक आगणन गठित किये जाय।
 - (12) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं० 2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
 - (13) निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होंगी।
2. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

अर्पण

स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में आय-व्ययक में अनुदान-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा -आयोजनागत-02- अ0सू0जा0 के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान-0201-अ0सू0ज0बाहुल्य क्षेत्रों में रा0हा0इ0कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण-24 -वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 650 (पी)/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2007 दिनांक 13.11.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. अपर सचिव, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. जिलाधिकारी, देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी।
9. कोषाधिकारी, देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी।
11. वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ।
12. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
13. संबंधित निर्माण एजेंसी।
14. कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
15. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
(पी0एल0शाह)
उप सचिव